

स्टेटमेंट भी 4 बजे है, वह कैसे होगा ?
(अवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has already been circulated that at 4 P.M. he will make a statement. You will please sit down.

RAO BIRENDRA SINGH: I announce the following decisions taken by the Government in respect of Price Policy for Wheat and Barley for 1980-91 crop season... (Interruptions)

(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only the Minister's statement will go on record. Nothing except the Minister's statement will go on record.

RAO BIRENDRA SINGH: (i) The procurement price for wheat has been increased from Rs. 117/- per quintal last year to Rs. 130/- per quintal this year. This amounts to a total increase of Rs. 13/- per quintal over the price paid last year and Rs. 3/- per quintal higher than the recommendation made by the Agricultural Prices Commission.

(ii) The issue price of wheat for Public Distribution System will be raised from Rs. 130/- per quintal to Rs. 145/- per quintal with effect from 1st April, 1981.

(iii) The issue price for Roller Flour Mills will be Rs. 155/- per quintal with effect from 1st April, 1981.

(iv) The present policy of free movement of foodgrains, including wheat, throughout the country will be continued. However, to maximise procurement of wheat, Government will, if necessary, impose levy on traders.

(v) As regard Barley, the support price has been fixed at Rs. 105/- per quintal as against Rs. 85/- per quintal recommended by the Agricultural Prices Commission

16.03 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DIS-
APPROVAL OF SPECIAL BEARER

BONDS (IMMUNITIES AND EXEMPTION) ORDINANCE, 1981 AND SPECIAL BEARER BONDS (IMMUNITIES AND EXEMPTIONS) BILL—contd.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Now, you have to put the Special Bearer Bonds Bill to the vote of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Statutory Resolution to the vote of the House.

The question is:—

"This House disapproves of the Special Bearer Bonds (Immunities and Exemptions) Ordinance, 1981 (Ordinance No. 1 of 1981) promulgated by the President on the 12th January, 1981."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I put the Motion for consideration, of the Bill to the vote of the House, there is an amendment which has to be disposed of.

I would like to know from Shri T. R. Shamanna whether he would like to withdraw it.

SHRI T. R. SHAMANNA: No, Sir. I want to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot speak. You can speak on Clauses and not now. I will put the amendment to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदेपर) :
उपाध्यक्ष महोदय, चार बजे चूके हैं, क्या
गुजरात कोमोशन नहीं लिया जायेगा ?
(अवधान)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: At 4 P.M. the discussion on Motion on Gujarat has to be started... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I want to complete it. I want to take the sense of the House.

श्री राजनाथ सोनेकर झारखी : क्या आप सदन को इस तरह से चलाना चाहते हैं ?

(Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. All of you please sit down. The Minister wants to say something. Please allow him to have his say.

(Interruptions).

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Motion is very important and, therefore, I do not want that there should be two opinions or controversy about it. Since we have got majority discussion on Bearer Bonds could have continued and voting would have taken place. But I do not want it. The issue is important and you can postpone the discussion and take up the Motion on Gujarat.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take discussion on the Motion on Gujarat. Shri Ram Vilas Paswan. . . .

16.08 hrs.

MOTION RE. SITUATION ARISING OUT OF AGITATION AND DEMONSTRATIONS RE-RESERVATION OF JOBS FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ : —

“कि यह सभा गुजरात, राजस्थान, और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए नौकरियों के आरक्षण के विरुद्ध आन्दोलन और हिंसात्मक प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करती है।”

उपाध्यक्षजी, . . . (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनेकर झारखी (सदर) : यह पता लग रहा है कि लोगों को इस से फिलती हमदर्दी है।

एक माननीय सदस्य: हमको बहुत हमदर्दी है।

श्री राजनाथ सोनेकर झारखी: आपको हम से ज्यादा नहीं होगी।

श्री राम विलास पासवान: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन काफी चर्चा हुई, मैं चाहूँगा कि आज जो चर्चा हो, उसमें कोई नतीजा निकले और हम लोग शान्तिपूर्ण ढंग से समस्या के समाधान के लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर विचार करें। सरकार से भी आग्रह है कि इस विषय को वह गंभीरता से ले और सरकार और गृह मंत्री महोदय द्वारा जो कुछ कहा जाए, वह बड़ी गंभीरता से कहा जाए। यह नहीं होना चाहिए कि 193 के तहत मौका मिल जाए और दूसरे दिन अखबारों में आ जाए कि गृह मंत्री महोदय ने यह कहा और फिर इसके बाद फिर मजबूत बढ़ता ही जाए और हाउस में हंगामा हो कि इस पर फिर डिस्कशन होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार बहुत ही गंभीरता से जवाब दे और गंभीरता से इस विषय को ले।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ, जितने भी माननीय सदस्य यहाँ पर हैं, उन्हें मालूम है कि उस समय अंग्रेजों द्वारा “डिवाइड एण्ड रूल” की पालिसी चलाई गई थी। उस समय अंग्रेजों द्वारा कमजोर वर्गों के दिमाग में यह चीज भर दी गई थी, हरिजन-आदिवासी और दलित वर्गों के लोगों के दिमाग में यह चीज बँटाने की कोशिश की गई थी कि यह देश तुम्हारा नहीं है और अगर तुम इस देश में रहोगे तो तुम्हारे जान-माल की सुरक्षा नहीं रहेगी। इसलिए तुम इस देश से अलग हो जाओ। आपको मालूम है कि उस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि महात्मा गांधी जी को आमरण अनशन पर जाना पड़ा था और उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान की जनता की तरफ से, हिन्दुओं और सब वर्गों की तरफ से अछूतों को विश्वास दिलाया था कि तुम्हारे अधिकार सुरक्षित हैं और इस देश में तुम्हें समान अधिकार दिए जाएंगे। हरिजन-आदिवासी, अल्प संख्यकों और कमजोर वर्गों के लोगों को पूरे अधिकार रहे और उपाध्यक्ष महोदय, यही कारण है जो हरिजन-आदिवासी और कमजोर वर्गों के अधिकारों को न सिर्फ क्वैटिडेशन में